



## न्यूज ब्रीफ

राजीव बने बजरंग दल  
के जिला सहसंयोजक

खुदांगंज, अमृत विचार : बजरंग दल

के जिला विधार्णी

प्रमुख राजीव

कश्याकों को जिला

का सहसंयोजक

नियुक्त किया गया

है संगठन की दो

दिवसीय कार्य

मैं संगठन के प्रति लगन व मिष्ठा

को देखते हुए यह नियाय लिया गया

जिला सहसंयोजक बनाए जाने पर लोगों

ने हर्ष व्यक्त किया है।

खेत में जबरन बांधा

पोस्ता, मारपीट

खुटार, अमृत विचार : क्षेत्र के गांव

गुरुरिया निवासी मध्याम ने पुरुषों को

तहीरी दी। बताया कि उसके 8 वर्षीय

पुरुष मंजीत के नाम गांव के किनारे 23

डिसम्बर खेत है। खेत के किनारे रहने

वाले एक व्यक्ति ने अपने दो पुत्रों के साथ

मिलकर उपर क्षेत्र में जबरन कच्चा

पेंस्टा बांध दिया। जह उसने शिकायत

की तो स्थानीय मारपीट पर आमदा

हो गए। आरोपी अपने घर की महिलाओं

को आगे कर विवाद करने लगे। शान

प्रभारी शमानीवार सिंह ने बताया कि जांच

कर कार्रवाई की जाएगी।

खाना बनाते समय कूकर

फटा, युवती धायल

खुटार, अमृत विचार : नगर के मोहल्ला

गांधीनगर निवासी बने दो पुरुष

गुलफिज सोमवार शाम करीब सात

बजे कूकर में खाना बना रही थी। तभी

अचानक कूकर फटा गया और वह

उसकी चप्टी में आ गई। इसके हां पीर

सप्त धायल में गूँह गया। परिणाम

लुप्त करके तो लखनऊ के अस्पताल

ले कर चले गए हैं। जहां उसका इलाज

चल रहा है।

बछड़ा का कराया

इलाज, गोशाला भेजा

खुटार, अमृत विचार : खुटार-रूरानपुर

रोड पर सोमवार रात को अंजान वाहन

की ट्रकर से सड़क पार कर रहा बछड़ा

धायल हो गया। इलाज करने के बाद

उसे सिंहुरा गोशाला पहुँचा दिया गया है।

उसके हां पीर

गुलफिज सोमवार सात

बजे धायल में खाना बना रही थी। तभी

अचानक कूकर फटा गया और वह

उसकी चप्टी में आ गई। इसके हां पीर

सप्त धायल में गूँह गया। परिणाम

लुप्त करके तो लखनऊ के अस्पताल

ले कर चले गए हैं। जहां उसका इलाज

चल रहा है।

तीन शिकायतों में से दो का

मौके पर किया निस्तारण

जन सुनवाई दिवस में समस्याएं सुनते नगर आयुक्त डॉ. विपिन कुमार मिश्र।

कार्यालय संवाददाता, शाहजहांपुर

का निस्तारण किया गया। शेष

समस्याओं के निस्तारण के लिए,

त्वारक कार्यालय के नियाम की गई।

जिसमें नगर क्षेत्र के लोगों ने साफ-

सफाई, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति,

प्रकाश बिन्दु, नाली निर्माण एवं

अधिकारी डॉ. मनोज कुमार मिश्र,

महाप्रबंधक जल विद्युत नारायण

मौय, लेखांशुकारी नेरेंद्र प्रतप सिंह

व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

अमृत विचार : नगर आयुक्त डॉ.

विपिन कुमार मिश्र की अध्यक्षता

में मंगलवार को नगर नियाम

कार्यालय में जन सुनवाई की गई।

जिसमें नगर क्षेत्र के लोगों ने साफ-

सफाई, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति,

प्रकाश बिन्दु, नाली निर्माण एवं

अधिकारी डॉ. मनोज कुमार मिश्र,

महाप्रबंधक जल विद्युत नारायण

मौय, लेखांशुकारी नेरेंद्र प्रतप सिंह

व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

अमृत विचार : क्षेत्र के अन्नपूर्णा

केंद्र पर मंगलवार को अचानक राशन

कार्ड धारकों से आधार कार्ड की फोटो

कॉपी मार्गी जाने तथा पंचायत सचिव

के मौखिक आदेश पर कोटेराव द्वारा

यह प्रक्रिया अपनाइ जा रही है, जिससे

उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का

सामना करना पड़ रहा है। कुछ कार्ड

धारक इस आदेश का विरोध कर

रहे हैं।

# विसंगतिपूर्ण समायोजन प्रक्रिया निरस्त करने की मांग

डीएम और बीएसए से शिक्षक नेताओं ने की वार्ता, मनमाने तरीके से शिक्षकों का समायोजन करने का लगाया आरोप।

कार्यालय संवाददाता, शाहजहांपुर



खुदांगंज, अमृत विचार : बजरंग दल

के जिला विधार्णी

प्रमुख राजीव

कश्याकों को जिला

का सहसंयोजक

नियुक्त किया गया

है संगठन के प्रति लगन व मिष्ठा

को देखते हुए यह नियाय लिया गया

जिला सहसंयोजक बनाए जाने पर लोगों

ने हर्ष व्यक्त किया है।

खेत में जबरन बांधा

पांडे, मारपीट

खुटार, अमृत विचार : बजरंग दल

के जिला विधार्णी

प्रमुख राजीव

कश्याकों को जिला

का सहसंयोजक

नियुक्त किया गया

है संगठन के प्रति

लगन व मिष्ठा

को देखते हुए यह नियाय

लिया गया

जिला सहसंयोजक

नियुक्त किया गया

है संगठन के प्रति

लगन व मिष्ठा

को देखते हुए यह नियाय

लिया गया

जिला सहसंयोजक

नियुक्त किया गया

है संगठन के प्रति

लगन व मिष्ठा

को देखते हुए यह नियाय

लिया गया

जिला सहसंयोजक

नियुक्त किया गया

है संगठन के प्रति

लगन व मिष्ठा

को देखते हुए यह नियाय





15 जनवरी को  
अवकाश, 28 नवम्बर  
को खुलेंगे न्यायालय  
बदायूं अमृत विचार : जनपद  
न्यायालय ने बताया कि उच्च  
न्यायालय, इलाहाबाद अदेशनुसार  
15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को मकर  
संक्रान्ति पर एवं जिला न्यायालयों में  
अवकाश घोषित किया गया है। मकर  
संक्रान्ति पर अवकाश हीनों की वज्र  
से एक वर्तुल शनिवार को कार्य दिवस  
घोषित कर्य किया जाएगा। इस घोषित  
अवकाश के एवज में 28 नवम्बर 2026  
वर्तुल शनिवार को समर्पण न्यायालय  
न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने हेतु  
खेल रहे होंगे। इसके अलावा 14 जनवरी  
एवं अवकाश शीमा में रह कर दिया  
है। 15 फरवरी को अवकाश घोषित  
किया है।

## दिव्यांगों को दुकान के लिए 30 हजार रुपए की मिलेगी सहायता

बदायूं अमृत विचार : जिला दिव्यांगजन  
सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार  
पाठक ने बताया कि दिव्यांगजन  
सशक्तिकरण विभाग में दुकान निर्माण/  
संचालन योजना चल रही है। योजना  
के तहत जनपद के ऐसे दिव्यांगजन  
जिनकी जन्मावजाहत 10 वर्ष से अधिक  
इससे अधिक है, तथा रोजगार  
करने के इच्छुक हैं वे जिन्हें पूर्व में इस  
योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे  
दिव्यांगजन को 10,000 रुपये दुकान  
संचालन के लिए व 20,000 रुपये  
दुकान निर्माण किये जाने के लिए दिया  
जाएगा। इसके बाद रहे 10 अन्नलाइन  
अपेनां बनाएंगे।

**युवाओं ने मनौना धाम  
तक शुरू की पदयात्रा**  
न्यूरपुर पिनौनी, अमृत विचार : भारत  
को 'हिंदू राष्ट्र' घोषित करने और  
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किये जाने  
की मांग को लेकर युवा ने अन्नलाइन  
पदयात्रा शुरू की है। पदयात्रा  
शुरू होने से पूर्व लोगों ने उत्तर प्रदेश  
माला पहनाकर रवानगत किया। पदयात्रा  
में कालू टांगु, मनू टांगु और देवेश  
कुमार सहित अन्य युवा शामिल हैं।

**पुलिस ने महिलाओं को  
किया जागरूक**  
कुरुगांव, अमृत विचार : पिलान शवित  
फेंज-5 अभियान के तहत मंगलवार  
को थाना पुलिस ने पैदल जवाहललाल  
नेहरू काँलेज सहित कर्षे में  
जागरूकता अभियान चलाया। महिला  
पुलिस द्वारा छात्राओं और महिलाओं  
को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।









बुधवार, 14 जनवरी 2026

## विफलता और प्रथन

पीएसएलवी-सी 62 मिशन मई 2025 में प्रक्षेपित पीएसएलवी-सी 61 मिशन की तरह ही असफल हो गया। इसरो की विगत उपलब्धियों और पीएसएलवी की 90 फीसद से ज्यादा सफलता के महेनज शक नहीं कि इसरो अपनी गलती सुधार कर भविष्य में ऐसे मिशन में कामयाब रहेगा। 64 प्रक्षेपणों में पांच विफलताएं बुरा प्रदर्शन नहीं। पीएसएलवी ने ही चंद्रयान-1 और आदित्य-एल 1 सेर वैधाला जैसे मिशनों को प्रक्षेपित किया था। पर इस मिशन की नाकामी ने इसरो की प्रतिष्ठा, पीएसएलवी की क्षमताओं पर सवाल खड़ा किया है। अंतरिक्ष बाजार में तेजी से उभरते भारत की गति प्रगति को तात्कालिक तौर पर ही सी, झटका तो लगा है। इसके बाद के वित्तीय परिणाम सीरीज़ीय हैं। प्रियस्थानी वैश्विक प्रक्षेपण बाजार में इसरो पीएसएलवी को एक वैश्विक उत्पाद के तौर पर प्रस्तुत करता है। यह ईंगोएस-ए 1 प्रक्षेपण उपग्रह अवैध के साथ सात देशों के स्टार्टअप्स के अलावा शैक्षणिक संस्थानों की ओर से विकसित 15 अन्य पेलोड लेकर जा रहा था, सभी निष्ठ हो गए। स्वदेशी संस्थाओं की बात दीगर है, लेकिन विदेशी संस्थाओं का भरोसा इस दोहरी असफलता से क्षितिज डिगेगा। ऐसे में अंतरिक्ष बाजार की अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां पीएसएलवी के जेलिम का आकलन कर प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगी, इसरो का प्रक्षेपण कियायी नहीं रहेगा। चार चरणों वाले रोकेट पीएसएलवी-सी 62 पहले और दूसरे चरण में सामान्य रहा। तीसरे चरण के दौरान रोकेट नियन्त्रित प्रक्षेप पथ से हट गया। वह असामान्य रूप से घूमने लगा, जिसे “रोल रेट डिस्टर्सेंस” कहते हैं, इसके बाद वह अपेक्षित मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सका। संभवतः सी 61 मिशन के तीसरे चरण की तरह उसने भी “चैवर प्रेशर” खो दिया। नोजल या केंपिंग प्राणीयों में किसी संचानात्मक या सामग्री संबंधित विफलता भी इसकी वजह हो सकती है। नाकामी का कारण अपी स्पष्ट नहीं है, जान जारी है।

पिछले साल की विफलता की वजहें सार्वजनिक नहीं की गईं, फेल्योर एनालिसिस कमिटी की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में खाल रह गया। संभवतः रक्षा सुरक्षा मामलों को लेकर गोपनीयता बरती गई हो, ऐसे में इस बार भी उम्मीद कम ही है कि गलतियों की रिपोर्ट सामने आए। कुछ बरसों से नाकामी के विशेषण वाली रिपोर्टों को सार्वजनिक करना चाहिए। रिपोर्ट एसार्वजनिक होती तो पता चलता कि क्या कमियां थीं, उहाँ तीक करने के लिए क्या किया गया? इस बार बरत भरोसा दिलाया गया कि तीसरे चरण के डिजाइन को सुदूर किया गया है, लेकिन नाकामी ही हाथ आई। करदाता जनता और वैश्विक हितधारकों को यह जनने का पारा हक्क है कि 2025 में क्या गलत था? क्या 2026 में भी ऐसी ही गलती दोहराई गई और उसके बारे में फिर से क्यों प्रभावित हुआ? निजी उद्योगों के लिए अंतरिक्ष नियांग श्रेणी खोलने की भारतीय पीली पर भी इसन है, ये कीपी-कभार होने वाली गड़बड़ी नहीं है। फिलहाल, इसरो के लिए भरोसा फिर से कार्यम करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले नियमों एवं प्रक्रियाओं को दोबारा बनाने का मुश्किल काम शुरू कर देना चाहिए, जिसका सभी अच्छा तरीका तो यही हांगा कि अंतरिक्ष विभाग सी 61 मिशन की “फैलियर एनालिसिस कमेटी” द्वारा दी गई रिपोर्ट को जारी करे, जिससे विफलता का सटीक कारण जानकर सबक लिया जा सके।

### प्रसंगवथा

## मोटे अनाजों की खेती में बुंदेलखण्ड क्यों पिछड़ा

बुंदेलखण्ड की जलवायी, मिट्टी और पृष्ठभूमि मोटे अनाजों या जिन्हें हम मिलें भी कहते हैं, के अनुकूल था, लेकिन यह विचारणीय तथ्य है कि बुंदेलखण्ड से मोटे अनाजों की खेती क्यों गयाव सी हो गई है? सरसरी तीर पर देखें तो यह खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए सरकारी प्रयासों और हरित क्रिति के परिणामों का एक दृष्ट्यापन-सा दिखता है, परंतु इसके पीछे अनेक महत्वपूर्ण कारण हुए हैं, जो हमारी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक तौर पर हमारी सभ्यता मोटे अनाजों विशेषकर बाजार, ज्वार, कोदा, रागी, काकुन, कनकी, मक्का पर निर्भर थीं, क्योंकि वहाँ आसानी से उत्पादया जा सकता था। ये न सिर्फ पौधिक थे, बल्कि असाध जलवायु के लिए उपयुक्त भी थे, जिससे सिंचाई या ज्यादा शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, परंतु उत्पादन कम होने के कारण यह बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस समस्या के निवारण हेतु 1960 के दशक में शूरू हुई हरित क्रिति का उद्देश्य

वैश्विक स्तर पर खाद्य उत्पादन को बढ़ाकर लोगों की खाद्य सुकृति को सुनिश्चित करना था, जिसके लिए इसमें चावल और गेंहूँ जैसी अधिक उत्तम और अधिक कैलोरी प्रदान करने वाली फसलों को प्राथमिकता दी गई। स्वाभाविक रूप से सरकारों और वैज्ञानिकों ने इन अनाजों की विवेसित करने में भारी निवेश किया। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिए ससिद्धी, सिंचाई सुविधाएं और रासायनिक उत्तरक उपयोग कराया। उन्नत बीजों की अनुपलब्धता और अनुसंधान व विकास में निवेश की कमी के कारण मोटे अनाजों की खपत में भारी कमी आई।

शहरीकरण, खान पान में बदलाव और आधुनिक जीवनशैली से भी मोटे अनाजों के उपयोग में कमी आई। परिष्कृत गेंहूँ और पौलिश किए हुए चावल हमारे मुख्य भोजन बन गए। गेंहूँ और चावल को ‘बेहतर’ या उच्च सामान्य क्षमिता के लिए जाने लगा, जबकि मोटे अनाजों को ‘गरीबों का भोजन’ समझकर उपेक्षा की जाने लगी। भारत में वर्ष 1961 और वर्ष 2011 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कुल अनुपात 35 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 17 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गया। मोटे अनाजों की कम कम बीमी रही। स्वाभाविक रूप से इसकी खेती में धीरे-धीरे गिरावट आ गई। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1983 से वर्ष 2011 के बीच भारत मंडराया और ग्रामीण दोनों ही परिवरों में मोटे अनाजों की खपत में भारी कमी आई।

शहरीकरण, खान पान में बदलाव और आधुनिक जीवनशैली से भी मोटे अनाजों के उपयोग में कमी आई। परिष्कृत गेंहूँ और पौलिश किए हुए चावल हमारे मुख्य भोजन बन गए। गेंहूँ और चावल को ‘बेहतर’ या उच्च सामान्य क्षमिता के लिए जाने लगा, जबकि मोटे अनाजों को ‘गरीबों का भोजन’ समझकर उपेक्षा की जाने लगी। भारत में वर्ष 1961 और वर्ष 2011 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कुल अनुपात 35 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 17 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गया। मोटे अनाजों की कम उत्पादकता कम बीमी रही। स्वाभाविक रूप से इसकी खेती में धीरे-धीरे गिरावट आ गई। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1983 से वर्ष 2011 के बीच भारत मंडराया और ग्रामीण दोनों ही परिवरों में मोटे अनाजों की खपत में भारी कमी आई।

शहरीकरण, खान पान में बदलाव और आधुनिक जीवनशैली से भी मोटे अनाजों के उपयोग में कमी आई। परिष्कृत गेंहूँ और पौलिश किए हुए चावल हमारे मुख्य भोजन बन गए। गेंहूँ और चावल को ‘बेहतर’ या उच्च सामान्य क्षमिता के लिए जाने लगा, जबकि मोटे अनाजों को ‘गरीबों का भोजन’ समझकर उपेक्षा की जाने लगी। भारत में वर्ष 1961 और वर्ष 2011 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कुल अनुपात 35 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 17 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गया। मोटे अनाजों की कम उत्पादकता कम बीमी रही। स्वाभाविक रूप से इसकी खेती में धीरे-धीरे गिरावट आ गई। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1983 से वर्ष 2011 के बीच भारत मंडराया और ग्रामीण दोनों ही परिवरों में मोटे अनाजों की खपत में भारी कमी आई।

शहरीकरण, खान पान में बदलाव और आधुनिक जीवनशैली से भी मोटे अनाजों के उपयोग में कमी आई। परिष्कृत गेंहूँ और पौलिश किए हुए चावल हमारे मुख्य भोजन बन गए। गेंहूँ और चावल को ‘बेहतर’ या उच्च सामान्य क्षमिता के लिए जाने लगा, जबकि मोटे अनाजों को ‘गरीबों का भोजन’ समझकर उपेक्षा की जाने लगी। भारत में वर्ष 1961 और वर्ष 2011 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कुल अनुपात 35 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 17 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गया। मोटे अनाजों की कम उत्पादकता कम बीमी रही। स्वाभाविक रूप से इसकी खेती में धीरे-धीरे गिरावट आ गई। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1983 से वर्ष 2011 के बीच भारत मंडराया और ग्रामीण दोनों ही परिवरों में मोटे अनाजों की खपत में भारी कमी आई।

शहरीकरण, खान पान में बदलाव और आधुनिक जीवनशैली से भी मोटे अनाजों के उपयोग में कमी आई। परिष्कृत गेंहूँ और पौलिश किए हुए चावल हमारे मुख्य भोजन बन गए। गेंहूँ और चावल को ‘बेहतर’ या उच्च सामान्य क्षमिता के लिए जाने लगा, जबकि मोटे अनाजों को ‘गरीबों का भोजन’ समझकर उपेक्षा की जाने लगी। भारत में वर्ष 1961 और वर्ष 2011 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कुल अनुपात 35 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 17 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गया। मोटे अनाजों की कम उत्पादकता कम बीमी रही। स्वाभाविक रूप से इसकी खेती में धीरे-धीरे गिरावट आ गई। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1983 से वर्ष 2011 के बीच भारत मंडराया और ग्रामीण दोनों ही परिवरों में मोटे अनाजों की खपत में भारी कमी आई।

शहरीकरण, खान पान में बदलाव और आधुनिक जीवनशैली से भी मोटे अनाजों के उपयोग में कमी आई। परिष्कृत गेंहूँ और पौलिश किए हुए चावल हमारे मुख्य भोजन बन गए। गेंहूँ और चावल को ‘बेहतर’ या उच्च सामान्य क्षमिता के लिए जाने लगा, जबकि मोटे अनाजों को ‘गरीबों का भोजन’ समझकर उपेक्षा की जाने लगी। भारत में वर्ष 1961 और वर्ष 2011 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कुल अनुपात 35 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 17 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गया। मोटे







